

मुकदमों का विवरण

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (2023 की आपराधिक अपील No.1030) 11 अगस्त, 2023

[एस. रवींद्र भाट और दीपांकर दत्ता, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:दोनों अपीलार्थियों-अभियुक्तों को क्रमशः यू/एस।411 और एस।120-बी, आई. पी. सी. काफी हद तक उनके और सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित था, जो समर्थन करने वाले साक्ष्य के साथ नहीं थे, यदि न्यायसंगत था।

साक्ष्य-यू/एस को दोषी ठहराने के लिए बिना किसी सहायक साक्ष्य के प्रकटीकरण बयानों पर भरोसा किया गया।411 और एस।120-बी, आई. पी. सी.-यदि पर्याप्त हो:

आयोजित किया गया:नहीं-हालाँकि प्रकटीकरण कथन किसी मामले को उलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक के रूप में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अपने आप में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और बिना किसी संदेह के आरोपों को घर लाने के लिए और कुछ भी नहीं हैं-दोनों अपीलकर्ता-अभियुक्तों ('एम' और 'के') के खिलाफ एकमात्र जोड़ने वाला सबूत उनके प्रकटीकरण बयानों के आधार पर वसूली थी, साथ ही अन्य सह-अभियुक्तों के बयानों के आधार पर, लेकिन यह सबूत एस के अर्थ के भीतर "तथ्य" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।27, साक्ष्य अधिनियम, 1872 और इस प्रकार, अविश्वसनीय-दंडनीय यू/एस के लिए क्रमशः अपीलार्थियों की दोषसिद्धि।411 और एस।120-बी, आई. पी. सी. को अपास्त करना दिया गया, बरी कर दिया गया।[पैरा 21,30 और 44]

साक्ष्य अधिनियम, 1872 -एस. 27-प्रकटीकरण कथन यू/एस।27 अभियुक्त द्वारा बनाया गया-साक्ष्य मूल्य:

आयोजित किया गया:प्रदान की गई जानकारी प्रत्यक्ष रूप से खोजे गए तथ्य के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए, जिसमें भौतिक वस्तु, उसके मूल स्थान के बारे में विवरण और इन पहलुओं के बारे में आरोपी व्यक्ति की जागरूकता शामिल है-इसके अलावा, सह-अभियुक्तों के प्रकटीकरण बयानों के संबंध में, अदालतों ने पूरी तरह से उन पर भरोसा करने में संकोच किया है और उनका उपयोग केवल दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए किया है।[पारस 22 और 23] 247

246

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश का राज्य

साक्ष्य-संपत्ति जब्त करने के ज्ञापन-विश्वसनीयता:

आयोजित किया गया:सबूत का एक विश्वसनीय टुकड़ा हो सकता था लेकिन जब्ती के गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए-उनके बयानों के एक हिस्से पर भरोसा करने की कोई गुंजाइश नहीं थी-इस प्रकार, जब्ती ने विश्वसनीयता खो दी।[पैरा 26]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973-परीक्षा यू/एस।313** - विचारण न्यायालयों का कर्तव्य:

आयोजित किया गया:निचली अदालतों को आकस्मिक और सरसरी तरीके से बयान दर्ज करने के खिलाफ आगाह किया गया है-केवल आरोपी से पूछे गए प्रश्नों की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जिस सामग्री और तरीके से उन्हें तैयार किया गया है-वर्तमान मामले में, डकैती की मुख्य घटना के बारे में अप्रासंगिक और अमूर्त प्रश्न अपीलार्थी-आरोपी 'एम' से पूछे गए थे, भले ही उसकी कथित संलिप्तता बहुत बाद में हुई थी जब लूटी गई वस्तुओं को कथित रूप से सह-आरोपी द्वारा उसे बेच दिया गया था-अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सह-आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित है, लेकिन 'एम' को कभी भी परिस्थितियों को समझाने का अवसर नहीं दिया गया था।[पैरा 31 और 32]

साक्ष्य अधिनियम, **1872 -s.114 (a)**-अनुमान-घटना के दौरान अपीलार्थियों शिकायतकर्ता के घर पर मौजूद नहीं थे और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब यह पता चला कि 'एम' ने चोरी की वस्तुओं को खरीदा था और 'के' साजिश रचने में शामिल था:

आयोजित किया गया:तथ्य यू/एस की एक धारणा।114(क) अभिलेख पर अन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए तैयार किया जाना चाहिए और अन्य ठोस साक्ष्य से पुष्टि के बिना, इसे अलग से तैयार नहीं किया जाना चाहिए- विचारण न्यायालय ने एक धारणा के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त ('एम') में से एक को दोषी ठहराया।114(क) इस बात पर जोर देते हुए कि चोरी के तुरंत बाद चोरी की गई वस्तुओं का उसका कब्जा, इसकी चोरी की प्रकृति के ज्ञान के साथ, उसे यू/एस दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था।411, आई. पी. सी.-इसने अन्य कारकों पर विचार किए बिना तथ्य की इस तरह की धारणा बनाने में गलती की।[पारस 34-36]

दंड संहिता, **1860 -s.120-B**-सभी अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल एक अभियुक्त-अपीलार्थी ('के') को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया था।**120-बी-**वैधानिकता:

आयोजित किया गया:अकेले एक व्यक्ति को कभी भी आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि कोई अपने साथ साजिश नहीं कर सकता है-'के' यू/एस की सजा।120-बी दूषित।

[पैरा 38 और 41] 248 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

शब्द और वाक्यांश-"षड्यंत्र"-अर्थ-चर्चा-दंड संहिता, **1860 -s.120-A**। [पैरा 38]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184:[1964]

एस. सी. आर. 623-अनुसरण किया गया।

टोपानदास बनाम बॉम्बे राज्य (1955) 2 एससीआर 881; शिव कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) 9 एससीसी 676; संजीत कुमार सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1117; ए देवेंद्रन बनाम तमिल राज्य

नाडु (1997) 11 एससीसी 720:[1997] 4 पूरक।एस. सी. आर. 591-पर निर्भर।

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य (1995) पूरक (1) एस. सी. सी. 80:[1994] 1 पूरक। एस. सी. आर. 483; राम शरण चतुर्वेदी बनाम मध्य राज्य

प्रदेश (2022) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1080-संदर्भित।

पुलुकुरी कोटय्या और अन्य बनाम राजा-सम्राट 1946 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 47; ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67; सम्राट बनाम ललित मोहन चक्रवर्ती (1911) आई. एल. आर. 38 कैल 559; द किंग बनाम प्लमर (1902) 2 के. बी. 339; आई. जी. सिंगलटन वी.

राजा-सम्राट (1924-25) 29 CWN 260:ए. आई. आर. 1925 कैल 501-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील No.1030।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.2022 के निर्णय और आदेश से, 2019 के CRLA No.10549 में जबलपुर में प्रधान सीट।के साथ

2023 की आपराधिक अपील No.1458।

रूप:

हरमीत सिंह रूपरा, अमनकांत मिश्रा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।सनी चौधरी, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता।

249

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश का राज्य

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

दीपांकर दत्ता, जे।

1. ये आपराधिक अपीलें, विशेष अनुमति द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की पीठ ("उच्च न्यायालय", इसके बाद) के 12 अक्टूबर, 2022 के सामान्य निर्णय और आदेश पर हमला करती हैं, जिसके तहत 2019 की आपराधिक अपील संख्या 10474 और 2019 की आपराधिक अपील संख्या 10549 (दंड प्रक्रिया संहिता ("दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 374 (2) के तहत अपील। मनोज कुमार सोनी ("मनोज", इसके बाद) और कल्लू @हबीब ("कल्लू", इसके बाद) द्वारा ले जाए गए पीसी को क्रमशः बर्खास्त कर दिया गया। जबकि मनोज ने भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आई. पी. सी.", इसके बाद) की धारा 411 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपनी दोषसिद्धि पर हमला किया और तीन साल के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 5, 000.00 और तीन महीने की डिफॉल्ट सजा, कल्लू ने आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपनी सजा और दस साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ रु। 5, 000.00 और तीन महीने की डिफॉल्ट सजा।

2. कुल मिलाकर, कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को 28 नवंबर, 2019 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ("विचारण न्यायालय") के सामान्य निर्णय के अनुसार आई. पी. सी. के तहत दंडनीय विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उपरोक्त निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद, सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने 12 अक्टूबर, 2022 के सामान्य फैसले को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं ("एसएलपी", इसके बाद) को प्राथमिकता दी। तीन अभियुक्तों, सुलेमान, आरिफ और जयहिंद के एसएलपी को खारिज कर दिया गया और उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बिना किसी बाधा के छोड़ दिया। हालांकि, शेष दो अभियुक्तों, मनोज और कल्लू द्वारा पसंद की गई एसएलपी पर क्रमशः 06 अप्रैल, 2023 और 11 अप्रैल, 2023 को नोटिस जारी किया गया था।

3. इन दोनों अपीलों पर अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई हुई। हालांकि, एक सामान्य निर्णय हमले के अधीन होने के कारण, यह न्यायालय इस सामान्य निर्णय के माध्यम से इन दोनों अपीलों का निपटारा करने का प्रस्ताव करता है।

4. अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि पीडब्लू-18 ("शिकायतकर्ता", इसके बाद) द्वारा 14 अप्रैल, 2010 को लगभग 1 बजे इस आशय की शिकायत दर्ज की गई थी: 30 शाम को, जब शिकायतकर्ता अपने घर में थी, चार लोगों ने दरवाजे की घंटी बजाई। जब उसके नौकर, पीडब्लू-8 ने दरवाजा खटखटाया, तो पिस्तौल से लैस चारों व्यक्ति जबरदस्ती घर में घुस गए। उन्होंने 250 रु बनाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

शिकायतकर्ता और उसके नौकर के हाथ और पैर, उन्हें जान से मारने की धमकी देते थे, और लॉकर की चाबी लेकर शिकायतकर्ता से चांदी और सोने के गहने, नकदी और अन्य कीमती सामान लूटने के लिए आगे बढ़ते थे। अभियुक्त व्यक्ति 2 बजे तक शिकायतकर्ता के आवास पर रहे: 30 फ्लू ईडिंग से पहले पी. एम. शिकायत के आधार पर, लगभग 4 बजे एक एफ. आई. आर. दर्ज किया गया: 30 आई. पी. सी. की धारा 394 के तहत चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ और उन सभी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

5. एफ. आई. आर. की जाँच जाँच अधिकारी ("आई. ओ.", इसके बाद) द्वारा की गई थी। मनोज के खिलाफ विशिष्ट आरोप यह हैं कि चोरी किए गए गहने ("सामान", इसके बाद) कथित रूप से उसे बेच दिए गए थे और यह जानने के बावजूद कि सह-आरोपी ने उसे चोरी का सामान बेच दिया था, उसने फिर भी उसे बेईमानी से प्राप्त करने और रखने का विकल्प चुना। नतीजतन, उन्हें 9 मई, 2010 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, इन वस्तुओं को आई. ओ. द्वारा दो अलग-अलग दिनों-9 मई, 2010 और 21 मई, 2010 को बरामद किया गया। 9 मई, 2010 के जब्ती ज्ञापन में जब्ती गवाह पीडब्लू-16 और पीडब्लू-5 के हस्ताक्षर हैं, जबकि 21 मई, 2010 के जब्ती ज्ञापन में जब्ती गवाह पीडब्लू-11 और पीडब्लू-6 के हस्ताक्षर हैं। 15 जुलाई, 2010 को पीडब्लू-19, तहसीलदार द्वारा पहचान की प्रक्रिया का संचालन किया गया था। शिकायतकर्ता के पूर्व चालक कल्लू के खिलाफ विशेष आरोप अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ साजिश में शामिल होने से संबंधित हैं। उसके खिलाफ आरोप यह है कि उसने उनके साथ जानकारी साझा की, यह खुलासा करते हुए कि शिकायतकर्ता के पास उसके आवास में पर्याप्त राशि और मूल्यवान गहने थे, इस जानकारी के साथ कि वह अकेली रहती थी; इसके कारण कथित तौर पर शिकायतकर्ता के घर पर डकैती की योजना बनाई गई और उसे अंजाम दिया गया।

6. जाँच पूरा होने पर, मनोज और कल्लू सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। जिन अपराधों के लिए सभी अभियुक्तों पर आरोप लगाए गए थे, उन्हें निम्नानुसार दिखाया गया है:

जयहिंद	आई. पी. सी. की धारा 450, 394, 397 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1- बी)
आरिफ	आई. पी. सी. की धारा

	450,394,397 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी)
सुलेमान	आईपीसी की धारा 450,394,397
कल्लू	धारा 120-बी, आईपीसी
मनोज	आईपीसी की धारा 411

251

मनोज कुमार सोनी बनाम

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [दीपांकर दत्त, जे.] अपराध स्वीकार होने पर, आरोप तय किए गए और मनोज और कल्लू सहित अभियुक्तों ने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

7. शिकायतकर्ता की गवाही के आधार पर, यह स्थापित किया जाता है कि घटना के दौरान घटनास्थल पर मौजूद चार अभियुक्तों में से सुलेमान, आरिफ और जयहिंद की शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत पहचान की गई थी, लेकिन चौथे अभियुक्त की पहचान नहीं हो पाई थी। जांच के दौरान, यह पता चला कि चौथा आरोपी नाबालिग था और बाद में मामले को आगे की कार्यवाही के लिए किशोर न्यायालय में भेजा गया। जहाँ तक कल्लू और मनोज का संबंध है, वे घटना के दौरान शिकायतकर्ता के घर पर मौजूद नहीं थे और जांच के बाद के चरण में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जब यह पता चला कि मनोज ने चोरी की वस्तुएँ खरीदी थीं और कल्लू साजिश रचने में शामिल था।

8. अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को निम्नलिखित रूप में दोषी ठहराया और सजा सुनाई:

जयहिंद और आरिफ	आई. पी. सी. की धारा 450,397 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी)	5 वर्षों के लिए 1,000 रुपये के आर. आई. के साथ 10 वर्षों के लिए 5,000 रुपये के आर. आई. के साथ 1,000 रुपये के चूक के साथ 1 वर्ष के लिए आर. आई.: 1 क्रमशः महीना, 3 महीने
-------------------	--	--

		और 1 महीना
सुलेमान	आई. पी. सी. की धारा 450,397।	5 साल के लिए 1,000 रुपये के आर. आई. के साथ 5,000 रुपये के डिफॉल्ट के साथ 10 साल के लिए आर. आई.: 1 महीना और 3 महीने, विशेष रूप से
कल्लू	धारा 120-बी, आईपीसी	5, 000 रुपये के डिफॉल्ट शुल्क के साथ 10 वर्षों के लिए आर. आई.: 3 महीनों
मनोज	आईपीसी की धारा 411	5, 000 रुपये की चूक के साथ 3 साल के लिए आर. आई.: 3 महीनों

9. मनोज को दोषी ठहराते हुए, विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से दो सबूतों पर भरोसा किया:जब्त ज्ञापन, जो मनोज के कब्जे से चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी पर तैयार किए गए थे, और पहचान पत्र ज्ञापन, जिसमें शिकायतकर्ता ने चोरी की गई वस्तुओं की पहचान की थी। विचारण न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 ("साक्ष्य अधिनियम", इसके बाद) की धारा 114 के तहत इस हद तक अनुमान लगाया कि "एक व्यक्ति जिसके पास चोरी के तुरंत बाद चोरी का सामान है, वह या तो चोर है या उसे यह जानते हुए सामान प्राप्त हुआ है कि वह चोरी हो गया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब न दे सके।" विचारण न्यायालय के अनुसार, मनोज के मामले में महत्वपूर्ण पुष्टि करने वाला सबूत यह था कि उसके कब्जे में पाई गई वस्तुएं शिकायतकर्ता की थीं और उसके द्वारा सटीक रूप से उनकी पहचान की गई थी।इसके अलावा, मनोज इस बारे में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे कि कैसे 252

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

चोरी का सामान उसके कब्जे में आ गया।इन सामूहिक कारकों के परिणामस्वरूप उन्हें आई. पी. सी. की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया गया।

10. जहाँ तक कल्लू का संबंध है, विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से आपराधिक साजिश के लिए उसकी दोषसिद्धि को दो प्रमुख कारकों पर आधारित किया:पहले, सह-अभियुक्त जयहिंद

द्वारा पूछताछ के दौरान 12 मई, 2010 के अपने ज्ञापन बयान में दी गई जानकारी, जिसमें कहा गया था कि उसने कल्लू को चोरी के पैसे से 3 रुपये, 000.00 दिए थे और उसके (कल्लू) घर/टप्रा में तीन गोलियों के साथ एक देशी पिस्तौल रखी थी; और दूसरा, पूछताछ के दौरान, कल्लू ने खुद अपने ज्ञापन बयान में अपने कमरे की अलमारी में 3 रुपये, 000.00 रखने की बात स्वीकार की, जिसे बाद में उसके खुलासे पर जब्त कर लिया गया। यह मानते हुए कि कल्लू ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ साजिश रची थी, विचारण न्यायालय ने उसे आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक साजिश का दोषी ठहराया। 11. उपरोक्त निर्णय को मनोज और उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश कल्लू द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद यह विचार था कि विचारण न्यायालय के निर्णय किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं और अपीलें किसी भी योग्यता से रहित थीं; इसलिए, उन्हें खारिज कर दिया गया था। मनोज की दोषसिद्धि और सजा को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि चोरी की गई अधिकांश वस्तुओं को उसके कब्जे से बरामद किया गया था और उनमें से कुछ को उसने पिघला दिया था। यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता द्वारा वस्तुओं की विधिवत पहचान की गई थी, उच्च न्यायालय का विचार था कि मनोज, यह जानते हुए कि वस्तुएं चोरी की गई संपत्ति थीं, उन्हें बेईमानी से बनाए रखा। कल्लू की दोषसिद्धि और सजा का समर्थन करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य का उल्लेख विद्वान कि शिकायतकर्ता कल्लू को जानता था और वह उसके चालक के रूप में काम कर रहा था और प्रकटीकरण बयान के आधार पर उसके घर से 3,000.00 रुपये बरामद किए गए थे।

दलों की प्रस्तुतियाँ

12. मनोज की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अवर न्यायालयों ने आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषसिद्धि दर्ज करने में गलती की। दोषसिद्धि को उलटने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत मुख्य प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

क) मनोज के घर से वस्तुओं की जब्ती/बरामदगी के दौरान उपस्थित सभी चार स्वतंत्र गवाह (पीडब्लू-5, पीडब्लू-6, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-16) मुकर गए और अभियोजन पक्ष के जब्ती के मामले का समर्थन करने में विफल रहे।

253

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश राज्य [दीपांकर दत्त, जे.] 254

आश्चर्य की बात है कि अवर न्यायालयों ने मामले के इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

ख) वस्तुओं के संबंध में पहचान प्रक्रिया के संचालन में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां थीं। संपत्ति की जब्ती के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, और शिकायतकर्ता और अभि. साक्षी 19 की गवाही से एक प्रक्रियात्मक साक्ष्य स्थापित किया गया है। मनोज के कब्जे से

आभूषणों की बरामदगी से यह साबित नहीं होता है कि वे शिकायतकर्ता के हैं। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत अनुमान को गलत तरीके से तैयार किया गया था क्योंकि पहचान प्रक्रिया गंभीर खामियों के लिए पर्याप्त थी।

ग) विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत मनोज का बयान दर्ज किया। पी. सी. बहुत ही अनौपचारिक तरीके से, जैसे कि यह कानून की औपचारिकता को पूरा कर रहा हो। यह मनोज के खिलाफ स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सबूत में दिखाई देने वाली किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को रखने में बुरी तरह विफल रहा। यह एक और प्रक्रियात्मक चूक है, और एक गंभीर चूक है, जिसने मुकदमे को दूषित कर दिया है।

घ) मनोज को उसके और पुलिस के बीच दुश्मनी के कारण मामले में फंसाया गया है क्योंकि पुलिस अक्सर [मनोज] को इधर-उधर जाने और आभूषणों का वजन करने, पहचान पत्र आदि दिलाने के लिए परेशान करती थी।” मनोज का यह बयान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उनकी जांच के अंत में दिया गया है। पी. सी. को अवर न्यायालयों ने बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया था।

ई) पुलिस गवाहों और जब्ती गवाहों की गवाही के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास मौजूद नहीं हो सकते हैं। विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से पुलिस गवाहों के बयानों पर भरोसा किया, रिकॉर्ड में उपलब्ध स्वतंत्र जब्ती गवाहों की अतिरिक्त गवाही की उपस्थिति की अनदेखी की, जो बाद में मुकर गए।

13. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि मनोज को आई. पी. सी. की धारा 411 के तहत दोषी ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए, मनोज की दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करना दिया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप, अपील को अनुमति दी जानी चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

14. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए दोनों अवर न्यायालयों ों ने अभिलेख पर सामग्री की गहराई से जांच की और साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में कोई भौतिक विरोधाभास नहीं पाया। उनके विरोधी द्वारा बताए गए प्रक्रियात्मक निर्णय के परिणामस्वरूप न्याय की कोई विफलता नहीं हुई और इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, जिसे तब से उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया है। मनोज की दोषसिद्धि और सजा का समर्थन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय से अपील को खारिज करने का आग्रह किया। 15. कल्लू की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने विवादित फैसले की शुद्धता को चुनौती दी और निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं: क) शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाए जाने के अनुसार कल्लू की ओर से किसी भी अपराध को करने की कथित

साजिश को साबित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया था। दूसरे शब्दों में, आई. पी. सी. की धारा 120-ए, आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध के आवश्यक तत्व स्थापित नहीं किए गए थे।

ख) विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए बयानों और जानकारी के आधार पर अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया। हालाँकि, शिकायतकर्ता ने कल्लू के खिलाफ कोई बयान या आरोप नहीं लगाया। उनका विश्वास केवल दो तथ्यात्मक पहलुओं पर आधारित था: पहला, आरोपी जयहिंद द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जांच के दौरान उससे 3 रुपये, 000.00 बरामद किए गए थे और दूसरा, कल्लू एक साल पहले शिकायतकर्ता का चालक हुआ करता था। इन परिस्थितियों के अलावा, अभियोजन पक्ष आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत आरोप को साबित करने के लिए कोई अतिरिक्त सबूत पेश करने में विफल रहा; इसलिए दोषसिद्धि और सजा, केवल इन आधारों पर कायम नहीं रह सकती है।

ग) सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य 1 को समर्थन के लिए रखा गया था।

यह तर्क कि कल्लू और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच अपराध करने के लिए एक समझौते के आवश्यक तत्वों की कमी है, जो आपराधिक साजिश के आरोप को घर लाने के लिए एक आवश्यक घटक है। इसके अतिरिक्त, राम शरण चतुर्वेदी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2 पर समझौते की किसी प्रकार की भौतिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पर जोर देने के लिए भरोसा किया गया था।

1 (1995) पूरक (1) एस. सी. सी. 80

2 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 1080 255

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश राज्य [दीपांकर दत्त, जे.] 256

आपराधिक षड्यंत्र स्थापित करने के लिए। तोपंदास बनाम बॉम्बे राज्य 3 को इस तर्क का समर्थन करने के लिए रखा गया था कि अकेले एक व्यक्ति को कभी भी आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ साजिश नहीं कर सकता है। यह बताया गया कि वर्तमान मामले में कल्लू एकमात्र व्यक्ति है जिसे आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि किसी अन्य आरोपी को इसी प्रावधान के तहत दोषी नहीं ठहराया गया है, जिससे कल्लू की दोषसिद्धि की वैधता के बारे में गंभीर संदेह पैदा होते हैं।

घ) अवर न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में महत्वपूर्ण भौतिक विरोधाभासों, सुधारों और चूक की अनदेखी की है।

16. तदनुसार, विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई थी कि अपील की अनुमति दी जाए, और कल्लू पर दर्ज दोषसिद्धि और दी गई सजा अपास्त करना कर दिया जाए।

17. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर रखी गई सभी सामग्रियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा है। अपीलार्थी कल्लू द्वारा हस्तक्षेप के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किए जाने के कारण, विद्वान अधिवक्ता ने अपील को खारिज करने का अनुरोध किया।

विश्लेषण और निष्कर्ष

18. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर सामग्री का भी अध्ययन किया है।

19. इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि मनोज और कल्लू पर मुकदमा चलाने के लिए वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य की गुणवत्ता उन्हें दोषी ठहराने के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय थी और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी नहीं करने में गलती की।

प्रकटीकरण वक्तव्य

20. मामले के तथ्यों से पता चलता है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने आई. ओ. को खुलासा बयान दिए, जिसके बाद धन, आभूषण आदि की बरामदगी की गई। हालांकि यह काफी असामान्य है कि सभी अभियुक्त, गिरफ्तार होने के बाद, आई. ओ. को वसूली करने के लिए स्थानों पर ले जाते हैं।

3 (1955) 2 एससीआर 881

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

चोरी की गई वस्तुओं पर, हम केवल इस आधार पर अभियोजन पक्ष की याचिका पर अविश्वास करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। मनोज की संलिप्तता मुख्य रूप से सह-आरोपी सुलेमान और जयहिंद द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित थी, जिसमें उन्होंने चोरी की वस्तुओं को उसे बेचने की बात स्वीकार की थी और खुद मनोज द्वारा दिए गए इसी तरह के बयान के कारण धारा 27, साक्ष्य अधिनियम के तहत वसूली हुई थी। इसी तरह, नीचे की दोनों अवर न्यायालयों ने कल्लू को दोषी ठहराते हुए, काफी हद तक स्वयं कल्लू के साथ-साथ सह-आरोपी जयहिंद द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान पर भरोसा किया, जिसने चोरी के पैसे से कल्लू को 3 रुपये, 000.00 देने और उसके घर/टप्रा में तीन गोलियों के साथ एक देसी पिस्तौल रखने की बात कबूल की।

21. एक संदेह पैदा होता है: क्या प्रकटीकरण बयानों को, किसी भी सहायक साक्ष्य के बिना, दोषसिद्धि प्राप्त करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है? हम इसे अविश्वसनीय समझते हैं। यद्यपि प्रकटीकरण कथन किसी मामले को उलझाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक के रूप में माने जाते हैं, हमारी राय में, वे अपने आप में पर्याप्त सबूत के रूप में इतने मजबूत नहीं हैं और उचित संदेह से परे आरोपों को घर लाने के लिए कुछ भी नहीं हैं।

22. स्वयं अभियुक्त द्वारा किए गए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत प्रकटीकरण बयानों के साक्ष्य मूल्य पर कानून अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है। पुलुकुरी कोटय्या और अन्य बनाम राजा-सम्राट 4 में प्रिवी काउंसिल का निर्णय आज भी अंतिम निर्णय रखता है जिसमें यह माना गया था कि प्रदान की गई जानकारी भौतिक वस्तु, उसके मूल स्थान और इन पहलुओं के बारे में आरोपी व्यक्ति की जागरूकता सहित खोजे गए तथ्य के लिए सीधे प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रिवी काउंसिल ने कहा: यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर पाया गया एक तथ्य एक प्रासंगिक तथ्य है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, दोषों को पढ़ने के लिए कोई औचित्य नहीं हो सकता है। 27 कुछ ऐसा जो वहाँ नहीं है, और एस द्वारा वर्जित एक स्वीकारोक्ति को साक्ष्य में स्वीकार करना। 26. उन मामलों को छोड़कर जिनमें किसी वस्तु को रखना या छिपाना आरोप का सार है, यह शायद ही कभी हो सकता है कि किसी तथ्य की खोज से संबंधित जानकारी अभियोजन मामले की नींव बनाती है। यह प्रमाण की श्रृंखला में केवल एक कड़ी है, और अन्य कड़ियों को कानून द्वारा अनुमत तरीके से जाली बनाया जाना चाहिए।

23. सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों के साक्ष्य मूल्य पर कानून भी तय हो गया है; अदालतें पूरी तरह से इस पर भरोसा करने में संकोच करती हैं

4 1946 एससीसी ऑनलाइन पी. सी. 47; ए. आई. आर. 1947 पी. सी. 67 257

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश राज्य [दीपांकर दत्त, जे.] 258

सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान और उनका उपयोग केवल दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए किया गया था, जैसा कि सर लॉरेंस जेनकिंस ने सम्राट बनाम ललित मोहन चक्रवर्ती 5 में देखा, "एक सह-अभियुक्त के खिलाफ अन्य सबूतों को आश्वासन देने के लिए"।

हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य 6 में, इस न्यायालय ने

संविधान पीठ ने प्रकटीकरण बयानों से निपटने के दौरान अदालतों द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया:

13. ... एक आपराधिक मामले से निपटने में जहां अभियोजन पक्ष एक अभियुक्त व्यक्ति के दूसरे अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ स्वीकारोक्ति पर निर्भर करता है, अपनाए जाने का उचित दृष्टिकोण ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ अन्य साक्ष्य पर विचार करना है, और यदि उक्त साक्ष्य

संतोषजनक प्रतीत होता है और न्यायालय यह ठहराने के लिए इच्छुक है कि उक्त साक्ष्य उक्त अभियुक्त व्यक्ति के खिलाफ बनाए गए आरोप को कायम रख सकता है, तो न्यायालय इस दृष्टिकोण से स्वीकारोक्ति की ओर मुड़ती है कि वह अन्य साक्ष्य से जो निष्कर्ष निकालने के लिए इच्छुक है वह सही है।

24. दोषसिद्धि को बदनाम करने के एक और मामले में

धारा 411, आई. पी. सी., यह न्यायालय, शिव कुमार बनाम मध्य राज्य में

प्रदेश 7 ने धारा 411 के तहत दोषसिद्धि को पलट दिया, केवल सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों पर अनुचित निर्भरता रखने से इनकार कर दिया, और कहा:

24. ..., एक अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान को इस बात के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी को बर्तनों के चोरी के सामान होने की जानकारी थी। अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के लिए यह विश्वास करने का कोई आधार स्थापित करने में भी विफल रहा है कि उसके पास से जब्त किए गए बर्तन चोरी की वस्तुएं थीं। बर्तनों को कम कीमत पर बेचने का तथ्य अपने आप में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपीलार्थी को उन वस्तुओं की चोरी के बारे में पता था। आई. पी. सी. की धारा 411 के तहत आरोप के लिए पुरुष रिया का आवश्यक घटक स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है। इस पहलू पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, जैसा कि वे मर्चेन्ट ऑफ वेनिस में ग्रेटियानो के चरित्र की बात करते हैं, को उचित रूप से इस रूप में वर्णित किया जा सकता है, "आप कुछ भी नहीं बोलते हैं।" [विलियम शेक्सपियर, मर्चेन्ट ऑफ वेनिस, अधिनियम 1 दृश्य 1।] 25. मामले पर आते हुए, मनोज और सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयानों के अलावा सबूत का एक भी अंश नहीं है, जो

5 (1911) आईएलआर 38 कैल 559, पृष्ठ 588 6 एआईआर 1964 एससी 1184

7 (2022) 9 एस. सी. सी. 676

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

माना जाता है कि आई. ओ. ने मनोज से चोरी की गई वस्तुओं और कल्लू से 3 रुपये, <आई. डी. 1] की बरामदगी की। इस स्तर पर, हमें यह मानना चाहिए कि स्वीकार्यता और विश्वसनीयता दो अलग-अलग पहलू हैं और बाद वाला वास्तव में अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के मूल्यांकन का विषय है। पुलिस गवाहों के बयान स्वीकार्य होते, अगर वे अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते, और अगर कोई अन्य विश्वसनीय सबूत रिकॉर्ड पर लाया जाता। जबकि आई. ओ. द्वारा धारा 27, साक्ष्य अधिनियम के तहत मनोज, कल्लू और अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा प्रकटीकरण बयानों पर की गई बरामदगी को तथ्यों की खोज का कारण माना जा सकता है और यह स्वीकार्य हो सकता है, इसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों को देखते हुए विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

26. जबकि संपत्ति जब्ती ज्ञापन मनोज की दोषसिद्धि के समर्थन में सबूत का एक विश्वसनीय टुकड़ा हो सकता है, जो हुआ है वह यह है कि जब्ती के गवाह 'जाओ' शब्द से शत्रुतापूर्ण हो गए। सभी जब्ती गवाहों, यानी पीडब्लू 5,6,11 और 16 का सामान्य संस्करण यह था कि उन्हें 'दरोगा' के आग्रह पर जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था और वह भी, उनमें से दो ने पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार, उक्त पीडब्लू 5,6,11 और 16 के बयानों के एक हिस्से पर भरोसा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार देखे जाने पर, जब्ती विश्वसनीयता खो देती है।

27. संजीत कुमार सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में यह न्यायालय 8

आयोजित: 18. लेकिन यदि न्यायालय को-(i) स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुलिस गवाहों की गवाही की पुष्टि की कमी की पूरी तरह से अवहेलना करनी है; और (ii) स्वतंत्र गवाहों के प्रतिकूल होने पर नेल्सन की नज़र डालनी है, तो अभियोजन पक्ष की कहानी बहुत विश्वसनीय होनी चाहिए और आधिकारिक गवाहों की गवाही विशेष रूप से भरोसेमंद होनी चाहिए। यदि स्वतंत्र गवाह एक ऐसी कहानी के साथ आते हैं जो अभियोजन पक्ष के सिद्धांत में, खोज और जब्ती के बारे में एक अंतर पैदा करती है, तो अभियोजन पक्ष का मामला ताश के पत्तों की तरह गिर जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि हमेशा आवश्यक नहीं होती है। लेकिन एक बार जब अभियोजन पक्ष एक कहानी के साथ सामने आता है कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तलाशी और जब्ती की गई थी और वे न्यायालय के समक्ष उनसे पूछताछ करने का भी विकल्प चुनते हैं, तो न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या स्वतंत्र गवाहों का बयान जो शत्रुतापूर्ण हो गए हैं, अविश्वसनीय है और क्या इस बात की संभावना है कि वे दलबदलू बन गए हैं।

8 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1117 259

मनोज कुमार सोनी बनाम

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [दीपांकर दत्त, जे.] 260

28. हम इस दृष्टिकोण की ओर झुकाव रखते हैं कि जब्त किए गए गवाहों की गवाही, वर्तमान मामले में एकमात्र धागा है जो ढीली माला को एक साथ बांध सकता है, और इसके बिना, चोरी की संपत्ति की जब्ती ही गलत साबित होती है। हम इस परिस्थिति के महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सभी चार स्वतंत्र जब्ती गवाह (पीडब्लू 5,6,11 और 16), जो कथित रूप से मनोज के घर से चोरी की वस्तुओं की जब्ती/बरामदगी के दौरान मौजूद थे, मुकर गए और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं कर रहे थे, जब्ती पर आई. ओ. के स्वतंत्र साक्ष्य को निर्णायक या आश्वस्त करने वाला नहीं माना जा सकता है। इसलिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उसके द्वारा की गई बरामदगी को अस्वीकार किया जाना चाहिए। 29. कल्लू के मामले में भौतिक विसंगति आई. ओ. और शिकायतकर्ता के बयानों में विरोधाभास है। आई. ओ. ने बयान दिया कि सह-अभियुक्त जयहिंद द्वारा खुलासा किए जाने पर, उसने सफलतापूर्वक रु। 3, 000.00 (जिसमें तीन एक हजार रुपये के नोट शामिल थे),

गवाहों की उपस्थिति में उसे जब्त कर लिया, और एक जब्ती पंचनामा तैयार किया; हालाँकि, जब कोई शिकायतकर्ता के बयान को देखता है, तो यह पूरी तरह से असंगत है। उसने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि आरोपी व्यक्ति उसके घर से एक हजार रुपये का कोई नोट नहीं ले गए। यह हमारे ध्यान से नहीं बचता है कि कल्लू की दोषसिद्धि पूरी तरह से रुपये की कथित वसूली पर निर्भर करती है। 3, 000.00 और नीचे की दोनों अवर न्यायालयों ने उसे आपराधिक साजिश का दोषी ठहराने के लिए इस पहलू पर बहुत अधिक भरोसा किया। हालाँकि, निचली अदालत के फैसले के अवलोकन से यह प्रतीत नहीं होता है कि वास्तव में जब्ती के गवाह कौन थे जिनकी उपस्थिति में रु। 3, 000.00 बरामद किया गया था, हालांकि ऐसा लगता है कि कई अभियोजन गवाहों में से कोई भी, जो गिरफ्तारी और जब्ती के गवाह थे, ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया था। हालाँकि सह-अभियुक्त जयहिंद, आरिफ और सुलेमान के अपराध को स्थापित करने के लिए कई अन्य सबूत हो सकते हैं, लेकिन मनोज और कल्लू को दोषी ठहराने के लिए विचार के योग्य कोई सबूत नहीं था।

30. यह स्पष्ट है कि मनोज और कल्लू के खिलाफ एकमात्र जोड़ने वाला सबूत अन्य सह-अभियुक्तों के साथ उनके प्रकटीकरण बयानों के आधार पर वसूली थी, लेकिन हमारी राय में, यह सबूत धारा 27 के अर्थ के भीतर "तथ्य" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साक्ष्य की ऐसी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम इसे पूरी तरह से अविश्वसनीय मानते हैं।

धारा **313, Cr.PC** के तहत वक्तव्य

31. मनोज के विचारण न्यायालय में एक और स्पष्ट दोष धारा 313, Cr.PC के तहत उसकी जाँच के इर्द-गिर्द घूमता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

मनोज द्वारा उत्तर के लिए तैयार किए गए प्रश्नों ने वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। हमें धारा 313, Cr.PC पर कई फैसलों में इस न्यायालय द्वारा कानून के स्पष्टीकरण को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें निचली अदालतों को आकस्मिक और सरसरी तरीके से बयान दर्ज करने के खिलाफ आगाह किया गया है। जो बात महत्वपूर्ण है वह केवल अभियुक्त से पूछे गए प्रश्नों की मात्रा नहीं है, बल्कि वह विषयवस्तु और तरीका है जिसमें उन्हें तैयार किया जाता है।

32. धारा 313, Cr.PC के तहत मनोज को दिए गए प्रश्नों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारण न्यायालय ने इस प्रक्रिया को एक खाली औपचारिकता के रूप में माना। उनकी दोषसिद्धि का आधार बनने वाली किसी भी भौतिक परिस्थिति को उनके सामने नहीं रखा गया था। आश्चर्यजनक रूप से, चोरी की गई वस्तुओं के बारे में उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। इसके बजाय, 14 अप्रैल, 2010 को हुई डकैती की मुख्य घटना के बारे में अप्रासंगिक और अमूर्त प्रश्न पूछे गए, भले ही उसकी कथित संलिप्तता बहुत बाद में हुई जब लूटी गई वस्तुओं को

सह-अभियुक्त द्वारा कथित रूप से उसे बेच दिया गया था। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर आधारित है, लेकिन मनोज को कभी भी परिस्थितियों को समझाने का अवसर नहीं दिया गया।

मनोज को आईपीसी की धारा **411** के तहत दोषी ठहराया गया

33. मनोज को आई. पी. सी. की धारा **411** के तहत दोषी ठहराया गया है जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना।—जो कोई भी बेईमानी से किसी भी चोरी की संपत्ति को प्राप्त करता है या अपने पास रखता है, यह जानते हुए या यह मानने का कारण है कि वह चोरी की संपत्ति है, उसे किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक की अवधि के लिए हो सकता है, या फिने, या दोनों के साथ।

34. विचारण न्यायालय ने मनोज को धारा **114 (ए)**, साक्ष्य अधिनियम के तहत एक धारणा के आधार पर दोषी ठहराया, जिसमें कहा गया कि चोरी के तुरंत बाद चोरी की गई वस्तुओं का उसका कब्जा, इसकी चोरी की प्रकृति की जानकारी के साथ, उसे आईपीसी की धारा **411** के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था। नतीजतन, उन्हें उक्त प्रावधान के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा **114** का दृष्टान्त (ए) ऊपर उल्लेख किया गया है लेकिन पूरा प्रावधान इस प्रकार है: “**114.** न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है।—न्यायालय विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है, जिसके होने की संभावना है। न्यायालय यह मान सकता है कि-(क) **261**

मनोज कुमार सोनी बनाम

मध्य प्रदेश राज्य [दीपांकर दत्त, जे.] **262**

चोरी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति के पास चोरी का सामान है, वह या तो चोर है या उसे यह जानते हुए सामान मिल गया है कि वह चोरी हो गया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब न दे सके।

***”

35. विचारण न्यायालय ने अन्य कारकों पर विचार किए बिना तथ्य की ऐसी धारणा बनाने में गलती की। वे कारक क्या हो सकते हैं

ए. देवेंद्रन बनाम तमिलनाडु राज्य **9** में इस न्यायालय द्वारा समझाया गया

निम्नलिखित शब्द:20. ... क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 114, दृष्टान्त (ए) के तहत एक धारणा किसी दी गई स्थिति में तैयार की जानी चाहिए, यह एक ऐसा मामला है जो साक्ष्य और मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चोरी की गई वस्तुओं की प्रकृति, मालिक द्वारा इसकी पहचान की प्रकृति, स्थान और इसकी वसूली की परिस्थितियाँ, घटना की तारीख और वसूली की तारीख के बीच की अवधि, जिन संबंधित व्यक्तियों से वसूली की जाती है, वे सभी कारक हैं जिन्हें निर्णय पर पहुंचने में ध्यान में रखा जाना चाहिए।

36. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (ए) के तहत तथ्य का एक अनुमान रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए और अन्य ठोस साक्ष्य से पुष्टि के बिना तैयार किया जाना चाहिए, इसे अलग से नहीं बनाया जाना चाहिए। वर्तमान मामला इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि विचारण न्यायालय को इस तरह की धारणा से क्यों बचना चाहिए था। मनोज की दोषसिद्धि, केवल अपने और अन्य सह-अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयानों पर निर्भर करती है, आई. पी. सी. की धारा 411 के तहत एक अनुमान के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मान लेना अनुचित नहीं होगा कि एक सुनार, जिसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर आभूषणों और आभूषणों का सौदा करना पड़ता है, उसके पास स्पष्ट रूप से उसकी दुकान में आभूषणों की एक महत्वपूर्ण मात्रा होगी। परिस्थितियों को देखते हुए, धारा 114 (ए) के तहत तैयार की गई ऐसी धारणा दूषित हो जाती है।

37. इस मोड़ पर, भले ही हम इस दावे की सच्चाई को मान लें कि मनोज को बेची गई वस्तुएं वास्तव में चोरी की गई वस्तुएं थीं, लेकिन आई. पी. सी. की धारा 411 को आकर्षित करना पर्याप्त नहीं होगा; जो और साबित करना आवश्यक था वह है ऐसी वस्तुओं को बेईमान इरादे और ज्ञान या विश्वास के साथ बनाए रखना कि वस्तुएं चोरी की गई थीं। अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित करने के लिए विचार के योग्य कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि मनोज ने लेखों को अपने पास रखा था

9 (1997) 11 एससीसी 720

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

या तो बेईमान इरादे से और चोरी की संपत्ति होने के ज्ञान या विश्वास के साथ।

कल्लू को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत दोषी ठहराया गया

38. यह दिलचस्प है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों में से केवल कल्लू को आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया है। इस स्तर पर, हम मदद नहीं कर सकते लेकिन आश्चर्य करते हैं: क्या कोई एकल व्यक्ति अपने साथ साजिश कर सकता है? हम असहमत हो सकते हैं। यह तार्किक रूप से इस प्रकार है कि अकेले एक व्यक्ति को कभी

भी आपराधिक साजिश का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि कोई साजिश नहीं कर सकता है।

स्वयं के साथ। ब्लैक लॉ डिक्शनरी (8 वें संस्करण) के अनुसार, 'षड्यंत्र' दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक गैरकानूनी कार्य करने के लिए एक समझौता है, जो समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने के इरादे से, और कार्रवाई या आचरण के साथ जुड़ा हुआ है।

यह समझौते को आगे बढ़ाता है। आई. पी. सी. की धारा 120-ए के शब्द इसे बहुत स्पष्ट करते हैं-आपराधिक साजिश का अपराध केवल तभी किया जाता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अवैध माध्यमों से किसी अवैध कार्य या कानूनी कार्य को करने या करने के लिए सहमत होते हैं। अंग्रेजी कानून में भी स्थिति अच्छी तरह से व्यवस्थित है। राजा बनाम प्लमर 10 में, राजा की पीठ ने लॉर्ड जस्टिस ब्रूस के माध्यम से बोलते हुए कहा:

यह तार्किक रूप से साजिश की प्रकृति का अनुसरण करता है कि, जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों पर एक दूसरे के साथ साजिश के साथ एक ही अभियोग में आरोप लगाया जाता है, और अभियोग में अन्य व्यक्तियों के साथ उनकी साजिश का कोई आरोप नहीं होता है, जो अभियोग में नामित नहीं हैं, तो, यदि अभियोग में नामित व्यक्तियों में से एक को छोड़कर सभी को बरी कर दिया जाता है, तो शेष व्यक्ति पर कोई वैध निर्णय नहीं दिया जा सकता है। (पृष्ठ 343)

39. आई. जी. सिंगलटन बनाम राजा-सम्राट 11 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय

आपराधिक साजिश से संबंधित कानून को और स्पष्ट किया गया: अंग्रेजी कानून का नियम जो अब अच्छी तरह से तय हो गया है, वह यह है कि जहां दो व्यक्तियों को एक साथ साजिश रचने के लिए आरोपित किया जाता है और उन पर एक साथ मुकदमा चलाया जाता है, दोनों को बरी कर दिया जाना चाहिए, या दोनों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। (पृष्ठ 265)

40. तोपेंदास (ऊपर) मामले में इस न्यायालय के निर्णय ने उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट किया और कहा:

14. ... आरोप पर क्योंकि यह इस मामले में अभियुक्त 1, 2, 3 और 4 के खिलाफ तैयार किया गया था, अभियुक्त 1 को अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सका

10 (1902) 2 के. बी 339

11 (1924-25) 29 सीडब्ल्यूएन 260: ए. आई. आर. 1925 कैल 501 263

मनोज कुमार सोनी बनाम

द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश [दीपांकर दत्त, जे.]

भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत जब उनके कथित सह-साजिशकर्ताओं आरोपी 2, 3 और 4 को उस अपराध से बरी कर दिया गया था। 41. कानून की उपरोक्त स्थिति को

ध्यान में रखते हुए, आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत कल्लू की दोषसिद्धि पूरी तरह से इस सरल कारण से दूषित है कि कोई अकेले साजिश नहीं कर सकता है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कल्लू और सह-अभियुक्त के बीच कोई समझौता हुआ था, जबकि कल्लू को छोड़कर अन्य किसी को भी आपराधिक साजिश के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।

निष्कर्ष

42. अमेरिकी इतिहासकार डैनियल जे. ब्रूस्टिन के शब्दों से अधिक उपयुक्त रूप से पूरे अभियोजन मामले को, विशेष रूप से मामले की जांच को संक्षेप में क्या कहा जा सकता था: “सबसे बड़ी बाधा

सच्ची खोज अज्ञानता नहीं है, बल्कि ज्ञान का भ्रम है।

43. इस पृष्ठभूमि में, यह कहना कि मनोज और कल्लू की दोषसिद्धि अभी भी कायम रह सकती है, दूर की बात लगती है; उनकी दोषसिद्धि को केवल अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में भ्रमक जानकारी के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

44. उपरोक्त सभी कारणों से, मनोज और कल्लू को बरी कर दिया जाता है और रिहा कर दिया जाता है। नतीजतन, विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज मनोज और कल्लू की दोषसिद्धि और उन पर लगाई गई सजा, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा लागू की गई थी, अपास्त करना दी गई है। मनोज और कल्लू अभी भी सलाखों के पीछे हैं। यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा। 45. तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है। कोई लागत नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे